(c)Detailed proposals are awaited.

(d)Does not arise.

Adverse Effect on Alloy Steel Plants Due to Fall in Rupee

1228. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent fall in the value of rupee in relation to dollar has adversely affected those Alloy Steel Plants which are dependent on imported raw materials;

(b) if so, the approximate amount of cost escalation per tonne of special steel in public and private sector plants; and

(c) in what manner the Ministry is contemplating to offset the incresed cost?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) A fall in the value of rupee will lead to an increase in import costs, ceteris paribus. However, no representations in this regard have been received from Alloy Steel Plants so far.

(b) and (c) The extent of increase in cost per tonne of special steel would depend upon the extent of dependence on imports. As this Ministry has not received any representation in this matter, there is no proposal to offset the increased cost presently under the consideration of this Ministry.

शिक्षा प्रदान करने के लिए भाषा माध्यम का सर्वेक्षण

1229. **श्री सोमपाल**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी उन विभिन्न भाषा माध्यमों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया हैं,जिनके माध्यम से देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) ऐसा सर्वेक्षण किस विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किस वर्ष में कराया गया था;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के आंकड़े प्रतिवर्ष एकत्र करती हैं;और

(ड़) यदि नहीं,तो उसके क्या कारण हैं;और क्या सरकार भविष्य में ऐसे आंकड़े एकत्र करना चाहेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा.कृपासिंधु भोई) : (क) और (ख) जी,हां । भाषाओं इत्यादि के संबंध में विवरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में उपलब्ध हैं ।

(ग) शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से वर्ष 1973,1986 और 1993 में अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण किए थे ।

(घ) जी,नहीं ।

(ड़) सर्वेक्षण शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से आवधिक रूप में किए जाते हैं ।

देश में पोलिटेक्रिक कालेज

1230. **प्रो.विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पोलिटेक्रिक कालेजों की राज्य-वार संख्या क्या हैं;

(ख) इन कालेजों में प्रति वर्ष कितने छात्रों को दाखिला मिलता हैं ;

(ग) इन कालेजों में प्रति वर्ष कितने छात्रों को डिप्लोमा मिला हैं;और

(घ) कितने डिप्लोमाधारी इस समय बेरोजगार हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.प.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी और फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु 184700 प्रवेश क्षमता वाले 1379 अनुमोदित पोलिटेक्रिक हैं । राज्यवार स्थिति विवरण के रूप में संलग्र हैं । (**नीचे देखिए**) वर्ष 1994-95 के दौरान डिप्लोमा प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या 90734 थीं । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बेरोजगार डिप्लोमाधारियों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती हैं ।

i विवरण

पोलिटेक्निकों की संख्या और उनकी प्रवेश क्षमता के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	फार्मेसी सहित पालिटेक्निकों की संख्या	प्रवेश संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	93	12,490
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	180
3.	असम	11	1,405
4.	बिहार	35	4,244
5.	गोवा	6	685
6.	गुजरात	43	7,235
7.	हरियाणा	36	4,575
8.	हिमाचल प्रदेश	10	690
9.	जम्मू और काश्मीर	18	2,824
10.	कर्नाटक	269	35,164
11.	केरल	60	7,043
12.	मध्य प्रदेश	54	7,243
13.	महाराष्ट्र	223	32,360
14.	मणिपुर	3	220
15.	मेघालय	1	150
16.	मिजोरम	1	110
17.	नागालैण्ड	1	90
18.	उड़ीसा	38	2,417
19.	पंजाब	57	6,586
20.	राजस्थान	38	3,118
21.	सिक्किम	1	60
22.	तमिलनाडु	154	29,849
23.	त्रिपुरा	2	165
24.	उत्तर प्रदेश	133	14,690
25.	पश्चिम बंगाल	46	5,520
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	150
27.	चंडीगढ़	4	560
28.	दादर व नगर हवेली	-	-
29.	दमन और दीव	1	90
30.	दिल्ली	33	4,856
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पांडिचेरी	5	634
	जोड़	1,379	1,84,700

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र

1231. **श्री राम देव भंडारी**: क्या कृषि मंत्री 12 मई,1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5646 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में स्थापित किए गए अनुसंधान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब ख़ान): दिनांक 12.5.1995 को राज्य सभा के जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया था,उसके संदर्भ में केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया हैं । [**देखिए परिशिष्ट** 175, **अनुपत्र संख्या** 31]

पशुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1232. **श्री गोपालसिंह जी.सोलंकी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1994-95 के लिए प्रत्येक योजना हेतु तय किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां,तो इस संबंध में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के बारे में ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) पशुपालन एंव डेयरी एक राज्य का विषय हैं । तथापि,पशुपालन के विकास के लिए उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एंव डेयरी विभाग विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा हैं । इन योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्र हैं । (**नीचे देखिए**)

(ख) इन योजनाओं का उद्देश्य देश में दूध,अण्डा तथा ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्वि करना हैं । वर्ष 1994-95 के लिए इन उत्पादों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं जिनके प्राप्त हो जाने की संभावना हैं ।

1994-95 के लिए लक्ष्य

1.दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)63.5

2.अण्डा उत्पादन (बिलियन में)26.1

3.ऊन उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.) 43.6

(ग) तथा (घ) जिलेवार/क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।